पेज थ्री देहरादून

हमारा दून

देहरादून, शनिवार 18 जनवरी, 2020

तूफान से प्रभावित परिवारों को चैक व कंबल वितरित करते मसूरी विधायक गणेश जोशी।

संक्षिप्त समाचार

दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण पर गोष्ठी 18 को

संवाददाता देहरादून। मंत्री दुग्ध विकास उत्तराखण्ड सरकार डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में ''राज्य में गठित दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढीकरण'' विषय पर 18 जनवरी को दून विश्वविद्यालय सभागार में प्रातः 11 बजे गोष्ठी का आयोजन किया गया है।

मेहूंवाला क्षेत्र में उल्लू पकड़ा

देहरादून **संवाददाता**। शिमला बाइपास स्थित मेहूंवाला क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा एक उल्लू पकड़ा गया। इन युवकों द्वारा पकड़े गए उल्लू के साथ सेल्फी भी खींची गई। उल्लेखनीय है कि उल्लू प्रतिबंधित प्रजाति का प्राणी है और इसे घर में नहीं रखा जा सकता। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में कुछ तांत्रिक सक्रिय हैं, जो कि युवाओं से तांत्रिक क्रिया के लिए उल्लू पकड़कर मंगाते हैं और फिर उसका प्रयोग तांत्रिक क्रिया में करते हैं। इसकी ऐवज में उल्लू पकड़कर लाने वाले युवाओं को मोटी रकम दी जाती है।

विधायक जोशी ने तूफान प्रभावित 19 परिवारों को राहत राशि के चैंक सौंपे

देहरादून **संवाददाता**। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने भारी बर्फबारी के बावजूद बुरासखण्डा में प्रभावित परिवारों को दैवीय आपदा के अर्न्तगत राहत राशि के चैक वितरित किये। भारी हिमपात की सम्भावना को देखते हुए विधायक जोशी यहां पर आईटीबीपी के वाहनों में सवार होकर गये थे। विगत दिनों तूफान के कारण ग्राम बुरासखण्डा में 19 परिवारों के मकानों की छत उड़ गयी थी, जिसके बाद विधायक जोशी के निर्देश पर जिला प्रशासन की टीम ने मौका मुआयना किया था।

वन प्रमाणीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

देहरादून **संवाददाता**। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग द्वारा राज्य के वन विभागों के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन "भारतीय संदर्भ में वन प्रमाणन" विषय पर किया गया। वन प्रमाणन दो अलग–अलग प्रक्रियाओं जैसे एफएमयू और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशन को संदर्भित करता है।

डब्ल्यूआईसी ने मनाया रस्किन बांड के कार्यों का जश्न

संवाददाता देहरादून। डब्लयूआईसी इंडिया देहरादून रुपा प्रकाशन और एलेफ बुक कंपनी के सहयोग से, देश के सबसे प्रिय लेखक, रस्किन बॉन्ड के कार्य की सराहना करते हुए उसका एक जश्न मनाया गया। इस दौरान रस्किन बॉड भी मुख्य रूप से मौजूद रहे और उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों के साथ अपने लेखन काल के कई अनुभव साझा किए।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर किया जायेगा विशेष प्रयास

बैठक

■ उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में बैठक

राज्यमंत्री धन सिंह रावत उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए।

संवाददाता

देहरादून। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने विधान सभा सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में बैठक की। डॉ0 धन सिंह रावत ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष प्रयास किया जायेगा तथा कॉलेजों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जायेगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कॉलेज को पूर्ण फैकल्टी, लैब, स्मार्ट क्लास की सुविधा से युक्त किया जायेगा तथा 2020 दिसम्बर तक 90 प्रतिशत कॉलेज अपने भवनों में शिफ्ट हो जायेंगे। प्रत्येक जनपद में मॉडल कॉलेज भी बनाया जायेगा। केन्द्र सरकार की कॉलेजों में एक भारत, श्रेष्ठ भारत, खेलो इण्डिया, स्वच्छता अभियान पर भी बल दिया जायेगा। उच्च शिक्षा पोर्टल पर कॉलेज की गतिविधियों संबंधी जानकारी मिलेगी और इस पर अपनी शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं। डॉ0 धन सिंह रावत ने कहा कि क्लास रूम में मोबाईल प्रतिबंधित करने के लिए शिक्षक, छात्र और अभिभावकों से सलाह ली जायेगी तथा इस विषय पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जायेगा।

तीन दिवसीय सभी कॉलेजों के टीचर्स ट्रेनिंग की व्यवस्था दो चरणों में मार्च 2020 तक पूर्ण कर ली जायेगी, इसमें पूर्व निदेशक को भी आमंत्रित किया जायेगा। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए देहरादून में अटल अकादमी भी बनायी जायेगी। इस अवसर पर निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 एनपी माहेश्वरी, पूर्व उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.एस.सी.पंत, डॉ. सविता मोहन और डॉ. एम.सी. त्रिवेदी आदि मौजूद थे।

जनपद स्तरीय अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण

देहरादून **संवाददाता**। शुक्रवार को पंचायतीराज विभाग द्वारा नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के दृष्टिगत जनपद स्तरीय अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आईआरडीटी सभागार सर्वे चौक देहरादून में प्रारम्भ हुआ। राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक कोटद्वार दिलीप रावत, विधायक पौड़ी मुकेश कोहली, विधायक, गंगोत्री गोपाल रावत एवं अपर सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज एचसी सेमवाल द्वारा दीप प्रज्जवलन कर कार्यशाला का शुभारम्भ किया गया। डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि ''भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को ग्राम स्तर पर प्रसारित करने हेतु इस प्रकार के प्रशिक्षण उपयोगी होते हैं तथा इनका समय–समय पर आयोजन किया जाना चाहिए।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील

अनुरोध

■सीएम ने राज्य स्टेट डाटा सेंटर के लिए अनुदान राशि की स्वीकृति का किया अनुरोध

केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात करते सीएम त्रिवेंद्र।

संवाददाता

देहरादून/नई दिल्ली। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से भेंट कर भारत नेट फेस–2 परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के प्रस्ताव व राज्य के स्टेट डाटा सेंटर के लिए अनुदान राशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि दूरसंचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत–नेट फेज–2 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाईबर के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जानी थी। यह योजना पूर्व में माह दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण होनी थी, जिसे तदोपरान्त मार्च, 2019 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। परियोजना पर कार्य आरम्भ न हो पाने के कारण यू.एस.ओ.एफ. (यूनिवर्सल सर्विसीस ओब्लिगेशन फण्ड) के स्तर से परियोजना को लोक निजी सहभागिता मॉडल पर क्रियान्वित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये थे। इसके अन्तर्गत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा लगभग रूपये 2700 करोड़ का प्रस्ताव दिया गया। पुनः यूएसओएफ द्वारा राज्य से आग्रह किया गया कि परियोजना का प्रस्ताव स्टेट लेड मॉडल के आधार पर प्रस्तुत किया जाये। इस आग्रह के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा रूपये 1914 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रस्ताव में परियोजना लागत पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा दिये गये प्रस्ताव से काफी कम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना नागरिकों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सरकार के लिये यह शीर्ष प्राथमिकता का विषय है। राज्य के क्षेत्र जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हैं व सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं, वहां भी कनेक्टिविटी पहुंचाना महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि भारत नेट फेस–2 परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के प्रस्ताव पर अनुमोदन देते हुए परियोजना के वित्त पोषण हेतु राज्य को धनराशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य ने नवीनतम तकनीकी हाईपर कन्वर्जड इन्फरास्ट्रक्चर पर आधारित प्रथम स्टेट डाटा सेंटर स्थापित कर क्रियाशील कर दिया है।

सड़क के चौड़ीकरण कार्य का मुआयना किया

सड़क चौड़ीकरण कार्य का मुआयना करते हुए।

देहरादून **संवाददाता**। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचन्द शर्मा की उपस्थिति में राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी के अधिकारियों ने प्रेमनगर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 के कि.मी. 143 में हो रहे सड़क के चौड़ीकरण क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया था ढांग कटिंग से स्थानीय निवासियों के आवासीय मकानों को हो रहे नुकसान का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों की शिकायतों को सही पाया तथा जिन लोगों के आवासीय मकानों को खतरा बना हुआ है उन्हें अन्यत्र जाने का सुझाव देते हुए विभाग की ओर से इस अवधि के किराये का भुगतान करने का भी आश्वासन दिया गया।

इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष लालचन्द शर्मा ने अधिकारियों से वार्ता कर सड़क के चौडीकरण से लोगों के आवासीय मकानों को हो रहे नुकसान से अवगत कराते हुए कहा कि सड़क के चौडीकरण के लिए हो रहे ढांग कटिंग कार्य के साथ–साथ पुस्ते का शीघ्र निर्माण होना चाहिए ताकि लोगों के आवासीय मकानों को हो रहे नुकसान से बचाया जा सके। इस पर वहां उपस्थित अधिकारियों द्वारा दो दिन के अन्दर पुस्ता निर्माण का आष्वासन दिया तथा उसके लिए सभी औपचारिकतायें पूर्ण करने का भी आश्वासन दिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।